



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522]
No. 522]

नई दिल्ली, भूगलबार, अक्टूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1999

आय-कर

सा.का.नि. 720(अ).— दूषित आय पर फर्दों के संबंध में दोहरे भराताब के परिकार एवं राजकोषीय अपर्वचन की रोकथाम के लिए भारत भूराज्य की सरकार और द्वितीयांत तथा टौरेंटो भूराज्य की सरकार के बीच अबूष्टीता अभिसमय दोबारे संविदाशी राज्यों द्वारा उक्त अभिसमय के अबूष्टित 29 के अबूष्टार उक्त अभिसमय को ताम्र फर्दे के लिए अपेक्षा फालूबां के अतर्गत अपेक्षित प्रशिक्षाओं को पूरा फर्दे के बारे में एक दूसरे को परवतीं अधिसूचनाओं के प्राप्त होके के तीस दिन के पश्चात् 13 अक्टूबर, 1999 को प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए अब आयकर अधिकारियम, 1961 । । 1961 फा 43। की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शरितयों फा प्रयोग फरते हुए फैलू सरकार एवं द्वारा यह बिदेश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपर्युक्त भारत संघ में ताम्र फिर जाएगी।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार
और राजस्व अपबंधन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

त्रिनिडाड और ट्रेबेगो गणराज्य की सरकार

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और त्रिनिडाड और ट्रेबेगो गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपबंधन को रोकने
के लिए और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को उन्नत करने की दृष्टि से एक अभिसमय
निष्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

व्यक्तिकक्ष सेवा

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के
निवासी हैं ।

अनुष्ठेद - 2

अभिसमय के अंतर्गत जाने वाले कर

1. यह अभिसमय किसी सौविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्रथिकरणों की ओर से आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे ये किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाष्यों पर लगाए गए करों और उधमों द्वारा अदा की जाने वाली मजदूरी अथवा केतनों की कुल राशियों पर करों के साथ-साथ पूँजी की मूल्यवृद्धि पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।

3. जिन गैजूदा करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :

(१) क्रिनिडाड और टेबेगो के मामले में, निगम कर, आयकर, बेरोजगारी बुल्क और पेट्रोलियम लैभ कर (जिन्हें इसके पश्चात् "क्रिनिडाड और टेबेगो कर" कहा जाएगा) ;

(२) भारत के मामले में, आयकर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिमार भी शामिल है (जिसे इसके पश्चात् "भारतीय कर" कहा जाएगा) ।

4. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा तत्क्षण समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् किसी सौविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ ३ में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रथिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद - ३

सामान्य परिवाधारं

१. इस अधिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

॥१॥ "त्रिनिडाड और टेबेगो" पद से अभिप्रेत है - त्रिनिडाड और टेबेगो का द्विप्रसमूही राज्य जिसमें त्रिनिडाड और टेबेगो के बहुत से द्विप्रसमूह इसके द्विप्रसमूही जलाशय, राज्य क्षेत्रीय समुद्र और इसके व्यायुमंडलीय क्षेत्र तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के निकटवर्ती अंतःसमुद्री क्षेत्र और इसके राज्य-क्षेत्रीय समुद्र से परे की महाविधिय जलगठन सीमा सम्प्रतित है जिन पर त्रिनिडाड और टेबेगो के कानूनों और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अपने प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार अथवा अन्य अधिकारों का प्रयोग करता है ;

॥२॥ "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्य क्षेत्र तथा उसमें इसके राज्य-क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के व्यायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिसमय सहित भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता-सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं ;

॥३॥ "एक सीधिदाकारी राज्य" तथा "दूसरा सीधिदाकारी राज्य" का अर्थ संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार त्रिनिडाड और टेबेगो गणराज्य अथवा भारत गणराज्य है ;

॥४॥ "ध्यक्ति" पद में कोई व्याप्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित सीधिदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक करायेय इकाई के रूप में समझा जाता है ;

॥५॥ "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है ;

॥६॥ "एक सीधिदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे सीधिदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से कम नहीं: एक सीधिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे सीधिदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

॥७॥ "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक सीधिदाकारी राज्य के निवासी किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान उक्त सीधिदाकारी राज्य के बीच ही चलाए जाते हों ;

॥४॥ "सक्षम प्रधिकारी" पद से अधिप्रेत है :

॥५॥ त्रिनिडाड और टेबेगो के मामले में, मंत्री जिसे कित्त के लिए जिम्मेदारी संभिं जाती है अथवा उसका प्रधिकृत प्रतिनिधि ;

॥६॥ भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्रधिकृत प्रतिनिधि ;

॥७॥ "राष्ट्रिक" पद से अधिप्रेत है :

॥८॥ एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता धारण करने वाला कोई व्यक्ति ;

॥९॥ कोई कानूनी व्यक्ति, भागीदारी अथवा संसद्या जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रदूत्त कानूनों से उस रूप में प्राप्त होती हो ;

॥१०॥ "वित्तीय वर्ष" पद से अधिप्रेत है :

॥११॥ त्रिनिडाड और टेबेगो के मामले में, "आय का वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम अध्याय 75:01 की धारा 2(1) में परिभाषित है ;

॥१२॥ भारत के मामले में, "पूर्वकर्त्ता वर्ष" जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित है ;

॥१३॥ "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा त्रिनिडाड और टेबेगो कर अधिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रूप शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिनके लिए यह अधिसमय लागू होता है अथवा जो इन करों के संबंध में लगाए गए अर्थ-वण्ड या जुर्माने के घोतक हैं ।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अधिसमय के प्रक्रिया में किसी शब्द का जो उसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा, जो उस समय उस संविदाकारी राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अधिसमय लागू होता है ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस अधिसमय के प्रयोजनार्थ "एक सौविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अधिकृत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य में उसके कानूनों के अनुसार उसके अधिकास, निवास, प्रबन्धन स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण कर लगता हो ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपर्योग के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही सौविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :-

- [(क)] उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक सम्बन्ध घनिष्ठतर हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- [(ख)] यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;
- [(ग)] यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;
- [(घ)] यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।

3. जहां व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ 1 के उपर्योग के कारण दोनों सौविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है । यदि उस राज्य, जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध-स्थान स्थित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो तो सौविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

मनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल हैं :

- १ क० प्रबन्ध का कोई स्थान ;
- २ स० कोई शासा ;
- ३ ग० कोई कार्यालय ;
- ४ घ० कोई कारसाना ;
- ५ ड० ६ कोई कार्यशाला ;
- ६ च० किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधापूर्ण मुहेया करता हो;
- ७ छ० कोई बिक्री बाजार ;
- ८ ज० कोई सान, तेल अथवा गैस का कोई कुआँ, कोई खदान अथवा प्रकृतेक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- ९ झ० प्रकृतिक संसाधनों की सोज अथवा विकास के लिए प्रयुक्त अथवा उनसे संबंधित कोई डिलिंग रिंग अथवा जलयान ;
- १० झ० कोई तलकर्षक परियोजना ;
- ११ ट० कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इनसे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हैं ;
- १२ ठ० कोई भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यावरणी कार्यकलाप, यदि ऐसा भवन स्थल परियोजना अथवा कार्यकलाप नी महीने से अधिक समय तक घलता रहता हो ।

3. इस मनुच्छेद के पूर्वांकी उपलब्धों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

- १ क० उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पर्यावरणी-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

- ॥५॥ मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित मात्र अथवा पर्यावरणीयों के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- ॥६॥ किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के मात्र अथवा पर्यावरणीयों के स्टॉक का रख-रखाव करना ;
- ॥७॥ उक्त उद्यम के लिए मात्र अथवा पर्यावरणीयों का केवल कार्य करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- ॥८॥ उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
- ॥९॥ उप-पैराग्राफ ॥१॥ से ॥८॥ तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बर्ती कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्यों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से बिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उक्त उद्यम का उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति की आवतन:-

- ॥१॥ उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ-३ में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो उस पैराग्राफ के उपर्यों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ; और
- ॥२॥ ऐसा प्राधिकार प्राप्त न हो किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे मात्र अथवा पर्यावरणीयों का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से मात्र अथवा पर्यावरणीयों की डिलीवरी करता हो ;
- ॥३॥ स्वयं उक्त उद्यम के लिए अथवा उक्त उद्यम के लिए और अन्य ऐसे उद्यमों के लिए पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः प्रथमोल्लिखित राज्य में आदेश प्राप्त करता है जो उस उद्यम की तरह नियंत्रण करते हों अथवा उसी तरह से नियंत्रित किए जाते हों अथवा उसी तरह के नियंत्रण के अधीन हों ।

5. इस अनुच्छेद के पूर्वकी उपबंधों के होते हुए भी किसी सीधाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम के पुनर्जीवा के मामलों को छोड़कर, दूसरे सीधाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि यह उस दूसरे राज्य के क्षेत्र में प्रियमयम पक्षत्र करता है अथवा स्वतंत्र हैसियत के प्लैन्ट से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जीवित कर बीमा करता है जिस पर पैराग्राफ 168 लागू होता है ।

6. किसी सीधाकारी राज्य में किसी उद्यम का मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी बलात, सामान्य कमीजन प्लैन्ट अथवा इकांत्र हैसियत वाले किसी अन्य प्लैन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, वर्तमान के ऐसे व्यक्ति उनके कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब किसी प्लैन्ट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा प्रयतः पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों तो वह ऐसी स्थिति में इस पैराग्राफ के अधिप्रयोग के अंतर्गत पक्ष स्वतंत्र हैसियत वाला प्लैन्ट नहीं समझा जाएगा ।

7. यदि कोई कम्पनी, जो एक सीधाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियोन्नित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियोन्नित होती है, जो दूसरे सीधाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में १ चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अग्रवा अन्यथा कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. किसी सीधाकारी राज्य के किसी नियासी द्वारा दूसरे सीधाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति १ कृषि अथवा बानिकी से प्राप्त आय सहित १ से प्राप्त आय पर भी दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ यही होगा जो अर्थ उक्त सीधाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत है, जिसमें विद्वाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और बानिकी में प्रयुक्त पशुपतन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपर्युक्त लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, श्रोतों और अन्य प्रकृतेक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अवायवियों के अधिकार । जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपर्युक्त, अचल सम्पत्ति के प्रयुक्त उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे ।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपर्युक्त, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक सौविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लाभों पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे।

2. ऐराग्राफ 3 के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, जहाँ एक सौविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सौविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थिति में वहाँ प्रत्येक सौविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक समान या उससे मिलती जुलती परीक्षितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता गिरेका यह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उस व्यय की कठैती की अनुमति वी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र उस राज्य के कर कानूनों के उपर्युक्तों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अधीन रहते हुए किए गए हों।

4. कोई लाभ, केवल इस कारण से स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा फ्य-वस्तुएं सहीदी है।

5. पूर्वकर्ता ऐराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को वर्णनुवर्ध उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ लाभों में आय की ऐसी मर्दै शामिल है जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपर्युक्त इस अनुच्छेद के उपर्युक्तों से प्रगतिशील नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8

जहाजरनी और वायु परिवहन

- एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा विमानों के प्रवालन से प्राप्त होने वाले लाभ के केवल उस राज्य में करायें होंगे ।
- कोई ऐसा परिवहन उद्यम, जो कि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, उसके द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में यात या पर्यावरणों के परिवहन के लिए प्रयुक्त आधानों एवं विसर्ग आधानों के परिवहन के लिए देलर और अन्य उपस्कर भी शामिल हैं। के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा किराए से प्राप्त लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जष्ट तक कि ऐसे आधानों का केवल अन्य संविदाकारी राज्य में प्रयोग नहीं किया जाता ।
- इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित नियियों पर ब्याज ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभों के स्वरूप में माना जाएगा और अनुच्छेद 11 के उपर्यंथ ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।
- पैराग्राफ 1 के उपर्यंथ, किसी फूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा अन्तरराष्ट्रीय प्रवालन एजेन्सी में भाग लेने से होने वाले लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

१क। एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

१ख। के ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूँजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ; और दोनों में से किसी भी अवश्या में दोनों उद्यमों के बीच उनके व्याख्यातिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगायी जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो के लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के उद्यम के लाभों में उन लाभों को शामिल करता है और तदनुसार उस पर कर लगाता है, जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार शामिल लाभ वह लाभ है जो कि प्रायमोहिलासित राज्य के उद्यम वजे प्राप्त होते यदि दोनों उद्यमों के बीच निर्धारित शर्तें के शर्तें होती जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच निर्धारित की गई होती,

तो उस दूसरे राज्य को उन लाभों में उसमें प्रार्थी कर की रांश के लिए समुचित समायोजन करना होगा । ऐसे समायोजन का निर्धारण करने के लिए इस अंतर्समय के अन्य उपलब्धों को भी ध्यान में रखना होगा और सौंधिकारी राज्यों के सहम प्रतिकारी, यदि आवश्यक हो, तो एक दूसरे से परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

- एक सौंधिकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे सौंधिकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे सौंधिकारी राज्य में करायें होंगे ।
- तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस सौंधिकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांश का हितभागी स्वभी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यह पैराग्राफ, उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिन लाभों में से लाभांश अदा किये जाते हैं ।
- इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अधिप्राय केयरों अथवा अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के रूप दावे न हों और इसमें अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय भी शामिल है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत केयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसकी किताब करने वाली कम्पनी निवासी है ।
- पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वभी जो एक सौंधिकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सौंधिकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र कैयकिंचित सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 जैसा भी मामला हो लागू होंगे ।
- जहां कोई कम्पनी, जो एक सौंधिकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सौंधिकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसी स्थिति में वह दूसरा राज्य उक्त कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर वहां तक किसी प्रकार का कर नहीं लगाया, जहां तक कि ऐसे लाभांश दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है और न ही उक्त कम्पनी के औक्तरित लाभों पर अवितरित लाभ संबंधी कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक सीधिदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सीधिदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा केप जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. किन्तु, इस प्रकार के ब्याज पर उस सीधिदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारीत कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । सीधिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस सीमा को लागू करने के तरीके का आपसी सहमति से निपटान करेंगे ।

3. पैराग्राफ १२४ के उपर्योगी के होते हुए भी, एक सीधिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज को उस दूसरे सीधिदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि यह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से अपने स्थानीय में रखा जाता है -

1. i) दूसरे सीधिदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्रशिकरण ; अथवा

2. ii) त्रिनिंदाड तथा टेबेगो के मामले में, त्रिनिंदाड तथा टेबेगो का सैन्ट्रल बैंक, कृष्ण विकास बैंक, निर्यात बीमा कम्पनी, राष्ट्रीय आवास प्राधिकरण, राष्ट्रीय बीमा बोर्ड, होम मोरटगेज बैंक, डिपोजिट बीमा कम्पनी, लघु व्यवसाय विकास कम्पनी, डेवलपमेंट फाइनेन्स लिंग तथा त्रिनिंदाड तथा टेबेगो मोरटगेज फाइनेन्स कम्पनी ।

3. iii) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत का निर्यात-आयान बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत का लघु उद्योग विकास बैंक तथा भारत का औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई.सी.आई.सी.आई.); अथवा

4. iv) कोई अन्य संस्था अथवा प्रौद्योगिक नियम पर दोनों सीधिदाकारी राज्यों के बीच आपसी सहमति हो ।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का आशय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह क्रांतक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और साम तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंध पत्रों अथवा ऋण पत्रों, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, जैसे पत्रों अथवा ऋण पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय, किन्तु इस अधिसमय के अनुच्छेद 10 के उपर्योगी के अधीन वितरण के रूप में मानी गई किसी घट की शामिल नहीं किया जाएगा । विलाप्त अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोगन के लिए दर्शान नहीं कराया जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक सौंधिदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सौंधिदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से ब्याप्ति करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र क्षेत्रिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋण दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्राप्ति रूप से संबंधित है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपर्युक्त, जैसा भी मामला हो, लागू होगी।

6. किसी सौंधिदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला वह स्वयं राज्य अथवा उस राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रधान, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति वश, चाहे वह एक सौंधिदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी सौंधिदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गयी है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपर्युक्त अंतिम वर्णित रूप पर लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के अंतिरिक्त भाग पर इस अधिसमय के अन्य उपर्योगों का साध्यक अनुपलब्ध करते हुए प्रत्येक सौंधिदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायहेट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक सौंधिदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सौंधिदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायहेट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायहेट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस सौंधिदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रायहेट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायहेट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 10 प्रतेशत से अधिक नहीं होगा।

3. ४क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त रायहिट्यां पद से दूरदर्थनि अथवा रोड्यो प्रसारण के संबंध में प्रयोग हेतु सिनेमा फिल्मों अथवा पुनोर्निर्माण के किसी माध्यम पर ऐकांडॅग सोहत किसी सांहेयिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के किसी कापिराइट, किसी ऐटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, जानकारी, कम्प्यूटर साप्टवेयर प्रोग्राम, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया अथवा किसी औदोगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित किसी सूचना के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायांगियां अधिसूचित हैं ॥

५स) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अधिसूचित तकनीकी अथवा अन्य कार्यकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सोहत कोई प्रबंध-कार्य, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायांगियां शामिल हैं परन्तु इसमें इस अधिसमय के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायांगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगी यदि रायहिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक सौंधेदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे सौंधेदाकारी राज्य में, जिसमें, रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयोक्तक सेवाएं करता है तथा जिस औषेकार अथवा सम्पर्क के संबंध में रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रगती रूप से संबद्ध है । ऐसे मामले में यथास्थाने अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे ।

5. एक सौंधेदाकारी राज्य में रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्राधीकरण या उस राज्य-का कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी सौंधेदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस सौंधेदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निर्माई गई हो और ऐसी रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायहिट्यां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायहिट्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गई होता, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध के बीच अंतर्मय व्योति रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायांगियों का आधेक्य भाग इस अधिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सौंधेदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार करायें होगा ।

अनुच्छेद -13

पूँजीगत अभिलाभ

- एक सौंवेदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लंशित और दूसरे सौंवेदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो किसी ऐसे स्थायी संस्थापन की कारबाहर सम्पत्ति का एक होस्सा है, जो एक सौंवेदाकारी राज्य के किसी उद्यम को दूसरे सौंवेदाकारी राज्य में उपलब्ध होती है अथवा किसी निर्विचित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक सौंवेदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे सौंवेदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयोक्तक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध होती है, जिसमें किसी ऐसे किसी स्थायी संस्थापन । अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ ॥ अथवा ऐसे निर्विचित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस पर दूसरे राज्य में भी कर लग सकेगा ।
- अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से एक सौंवेदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा ।
- किसी ऐसी कम्पनी के पूँजीगत स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर जिसकी सम्पत्ति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतया किसी सौंवेदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल होती है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- किसी ऐसी कम्पनी, जो कि एक सौंवेदाकारी राज्य को निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लंशित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लग सकेगा ।
- पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लंशित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी सौंवेदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवापं

1. एक सीधदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वस्प वाले अन्य कार्यकलार्पों से प्राप्त आय, नम्नलिखित परीक्षणों को छोड़कर, जिनमें ऐसी आय पर दूसरे सीधदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी सीधदाकारी राज्य में कराएय होगी :

१क। यदि उसे अपने कार्यकलार्पों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे सीधदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान निर्धारित स्प से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है ; अथवा

१ख। यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने को अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा उससे अधिक हो, तो उस मामले में आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलार्पों से प्राप्त होती है ;

१ग। यदि दूसरे सीधदाकारी राज्य में उसके कार्यकलार्पों के लिए पारिश्रमिक उस सीधदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अदा किया जाता है अथवा उस सीधदाकारी राज्य में रिश्ते किसी निश्चित स्थान अथवा स्थायी संस्थापन द्वारा वहन किया जाता है और उक्त वित्तीय वर्ष में 40,000 ₹० की राशि अथवा त्रिनिंदाढ़ और टेबेगो की करेंसी में इसके बराबर की राशि से अधिक हो जाती है ।

2. "व्यावसायिक सेवापं" पद में विशेष स्प से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सा-कर्मियों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविवरों, दंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 15

परावरताप्रियत वैयाकितक सेवाएँ

1. अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपर्युक्तों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त केन्द्रीय, भजदौरों, परिलम्बों और उस प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है यदि अन्योजन दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया है तो जो पारिश्रमिक वहाँ से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपर्युक्तों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोहत्तरांशित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, योद्धे :

१क। प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने वाली अथवा समाप्त होने वाली किसी बारह महीने की अवधि में कुल मैलाकर अधिक से अधिक 183 दिन की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहता है ; और

१स। पारिश्रमिक ऐसे किसी अन्योजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया जाता है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

१ग। पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निर्वाचित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो अन्योजक दूसरे राज्य में रखता हो ।

3. इस अनुच्छेद के पूर्वकर्ता उपर्युक्तों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पेत अथवा विमान पर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 16

निवेशकों की फीस

निवेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायागेयां जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निवेशक-मण्डल के सदस्य को हैंसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 17

मनोरंजनकर्ता और सिलाई

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपर्यों के होते हुए भी एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता जैसे कि कोई शियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी सिलाई के रूप में दूसरे सौविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के उसके ऐयकितक कार्यकलाएँ से प्राप्त आय पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी सिलाई द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए निजी कार्यकलाएँ के संबंध में प्राप्त आय इव्वर्य मनोरंजनकर्ता या सिलाई को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपर्यों के होते हुए भी, उस सौविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा सिलाई के कार्यकलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्त मनोरंजनकर्ता अथवा सिलाई द्वारा किसी सौविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्यकलाएँ से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य की यात्रा के लिए सौविदाकारी राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या स्थानीय प्राधिकरणों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्ततः समर्पित होती हों । ऐसे मामले में उक्त आय केवल उस सौविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका मनोरंजनकर्ता या सिलाई निवासी है ।

अनुच्छेद - 18

पैशन और सामाजिक सुख्ता अदायगियाँ

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपर्यों के अधीन एक सौविदाकारी राज्य के किसी निवासी को फिल्म नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पैशन और अन्य ऐसे परिश्रमिक और ऐसे निवासी को अदा की गई किसी कार्यक्रम पर भी उस राज्य में कर लगेगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपर्यों के होते हुए भी, अदा की गई पैशन और सार्वजनिक योजना के अंतर्गत की गई अन्य अदायगियाँ जो कि किसी सौविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुख्ता प्रणाली का भाग है, पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. **१क।** किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उसके उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन वे विन्न परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।

२स। तथापि, ऐसे परिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और व्यक्ति उस राज्य का निवासी है, जो :-

१।। उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा

२।। मात्र सेवाएं करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2. **१क।** किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

२स। तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल तभी लग सकेगा यदि व्यक्ति उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारबाह के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त परिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षा

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्याक्तिगतिक प्रशिक्षा को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दोरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, अनुवानों, झर्णों और छात्रवृत्तियों को छोड़कर, दूसरे राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

१क। उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पेशण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियां ; और

॥ ५ ॥ उस दूसरे राज्य में नियोजन से प्राप्त उत्तरी रकम का प्राप्त प्रतिफल जो उस रकम से अधिक न हो, जिस पर किसी कित्तीय वर्ष में उस अन्य सीविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत कर से छूट प्राप्त होती है, बश्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे तौर पर संबंधित हो या उसके भरण-पेशण के लिए किया जाता हो ।

२०. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के लाभ दूसरे सीविदाकारी राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार सात वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे ।

अनुच्छेद ~ 21

प्रेफेसर, अध्यापक और शोध अध्येता

१. कोई प्रेफेसर, अध्यापक शोध अध्येता जो दूसरे सीविदाकारी राज्य में अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल अथवा किसी अन्य संस्था में शिक्षण अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों ही प्रयोजनों हेतु उस दूसरे सीविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व उस सीविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था उसे उस दूसरे राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य संबंधी गतिविधियों के लिए प्राप्त होने वाले किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी ।

२. यह अनुच्छेद ऐसे शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ हेतु किया जाता हो ।

३. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक सीविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह उस कित्तीय वर्ष में उस राज्य का निवासी है जिसमें वह दूसरे सीविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उस कित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्व उसका निवासी था ।

४. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों हेतु "अनुमोदित संस्थाओं" का अर्थ किसी ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में उस राज्य के सक्रम प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो जिस राज्य में ऐसी संस्था स्थित हो ।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दें, जहां कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वका अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में ही कराधेय होंगी ।

2. ऐराग्राफ 1 के उपर्युक्त अनुच्छेद 6 के ऐराग्राफ 2 में यथापरिमापित अधल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे :

१क। यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय जदा की जाती है, वह उक्त स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्राप्ति स्प से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपर्युक्त, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ;

१ख। यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित लोतों से, लाटीरों, वर्ग-पहेलियों, घुइँदोइँ, कार्ड गोमों और किसी भी प्रकार के अन्य लोतों सहित ऐसी अथवा जुफ्लाजी अथवा किसी भी प्रकार या स्वस्प की भर्त लगाने से आय प्राप्त करता है तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगा सकेगा ।

3. ऐराग्राफ 1 और 2 के उपर्युक्तों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मर्दें जिन पर इस अभिसमय के पूर्वका अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया हो और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत हों, उन पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अधिकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य में प्रकृत कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान मामलों को अधिशासित करते रहेंगे सिवाए उन मामलों के जहां इस अभिसमय में उनके प्रतिकूल प्रक्षयान किए जाते हैं ।

2. त्रिनिंदाड और टेबेगो के मामले में, दोहरे कराधान का पीरहार निम्नानुसार किया जाएगा :-

जहां त्रिनिंदाड और टेबेगो का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपर्युक्तों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां त्रिनिंदाड और टेबेगो उस निवासी

की आय से भारत में अदा किए गए आयकर के बराबर की राशि की कटौती करने की अनुमति देंगे चाहे यह प्रत्यक्षतः दी जाए अथवा स्रोत पर कटौती के रूप में दी जाए ।

3. भारत के मामले में दोहरे कराधान का परिहार निम्नानुसार किया जाएगा :-

जहाँ भारत का कोई निक्षसी ऐसी आय ग्रहन करता हो जिस पर इस अमिसमय के उपर्युक्तों के अनुसार त्रिनिडाड और टेबेगो में कर लगाया जा सकता है वहाँ पर भारत उस निक्षसी की आय पर त्रिनिडाड और टेबेगो में अदा की गई आयकर के बराबर की रकम पर कर से कटौती की अनुमति देगा चाहे वह प्रत्यक्षतः दी जाए अथवा स्रोत पर कटौती के रूप में दी जाए । तथापि, ऐसी कटौती आयकर के उस अंश से, जो कटौती दिए जाने से पूर्व संगणित की जाती है, अधिक नहीं होगी जो उस आय से उद्भूत होती है जिस पर त्रिनिडाड और टेबेगो में कर लगाया जा सकता है ।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 में उल्लिखित संविदाकारी राज्य में देय कर में वह कर शामिल समझा जाएगा जो कि संविदाकारी राज्य के कानूनों के अधीन दिए जाने वाले उन कर प्रेत्साहनों के न होने पर देय होता और जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है ।

5. ऐसी आय, जिस पर इस अमिसमय के उपर्युक्तों के अनुसार किसी संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाता, उसे उस संविदाकारी राज्य में लगाए जाने वाले कर के दर की गणना करने के लिए शामिल किया जा सकता है ।

अनुच्छेद - 24

सम-प्रयवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी अपेक्षा को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर किसी ही परिणियतयों में लगाए जा रहे अथवा लगाए जा सकने वाले कराधान एवं तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत आंधक भारपूरा हो । अनुच्छेद 1 के उपर्युक्तों के होते हुए भी, यह उपर्युक्त उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के नियासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक-समान कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपर्युक्त का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन के लम्हों पर कर की ऐसी दर पर प्रभार लगाने से रोकना है जो उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही किसी कम्पनी के लम्हों पर लगाई जाती है और न ही इसका अर्थ यह होगा कि यह इस अमिसमय के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपर्युक्तों के प्रतिकूल हो ।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा परिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कठैतियों की मंजूरी दे जो यह अपने निवासियों को देता है।

4. ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 178 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 161 के उपर्युक्त लागू होते हैं, वहां एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त व्याज, रायहेट्यों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और अन्य संविक्तरणों को ऐसे उद्यमों के कर योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, उन्हीं शर्तों के तहत कठैती की अनुमति दी जाएगी जो प्रथमोहिलाखित राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोहिलाखित संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से तथा तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत भारपूर हो, जो उस प्रथमोहिलाखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर लागू हो अथवा लागू हो सकती हो।

6. अनुच्छेद 2 के उपर्योगों के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपर्युक्त प्रत्येक किलम और बेवरण के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि वोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा वोनों राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस अभिसमय के उपर्योगों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के देशीय कानूनों द्वारा उपर्युक्त उपायों का ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सकाम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है, अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के तहत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सकाम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन बर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके पीछामस्वरूप उस पर कर लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपर्योगों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सकाम प्राधिकारी को जापति उभित लगे और वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार के उद्देश्य से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सकाम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए करार को लागू किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के देशीय कानूनों में कोई समय-सीमा क्यों न हो।

३. इस अभिसमय के अर्थ-निरूपण में अथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाई या शंका उत्पन्न होती है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें परस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे ऐसे मायतों में भी दोहरे करायान को हटाने के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।

४. पूर्वकी ऐग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । इस अनुच्छेद में दिए गए परस्परिक करार विधि को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी परामर्श के माध्यम से उचित विधीय कार्यविधि, परीक्षण, पद्धति और तकनीक विकसित करेंगे ।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

१. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना ॥दस्तावेजों सहित॥ का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपर्यों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों से संबंधित स्वदेशी कानूनों के उपर्यों को कायांनिक करने के लिए आवश्यक है, जो इस अभिसमय के अंतर्गत आते हैं जहां तक कि उनके अधीन करायान व्यवस्था इस अभिसमय, विशेष रूप से ऐसे करों की योसाधी अथवा अपवंचन को रोकने, के प्रतिकूल नहीं हो । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद १ द्वारा प्रतिबोधित नहीं है । किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों ॥जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं॥ को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके बारे में प्रकर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने में शामिल हों, जो अभिसमय के अंतर्गत आते हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे । वे सूचना को सार्कजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते ।

२. किसी भी स्थिति में, ऐग्राफ १ के उपर्यों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

॥क॥ उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रश्न से हटकर प्रशासनिक उपय करना ;

॥स॥ ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों को भूमिया कराना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की समान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हैं ;

॥ग॥ ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्ताही करना जिससे कोई व्यापरिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिका संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसे प्रकट करना सार्कजनिक नीति के प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद - 27

राजनीतिक पौंट और अंसूली अधिकारी

इस अधिसमय की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अध्यक्षिकार वर्ग के उपर्योग के अंतर्गत राजनीतिक पौंट अथवा कांसूली अधिकारीयों के किसी विवेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 28

अंसूली में सहायता

1. किसी राजनीतिक दल के दूसरे को इस अधिसमय से संबंधित करों की अंसूली के साथ-साथ ऐसे करों से संबंधित व्याप, सागती और सिविल दंड की अंसूली में सहायता का व्यवन देते हैं जिन्हें इस अनुच्छेद में "राजस्व दाव" कहा गया है ।
2. किसी राजस्व दाव की अंसूली में किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता के लिए अनुच्छेद में ऐसे प्राधिकारी उत्त प्रभावन शामिल होगा कि उस राज्य के कानूनों के तहत राजस्व दाव को अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है । इस अनुच्छेद के प्रयोगनार्थ राजस्व दाव तभी अंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है जब किसी संविदाकारी राज्य को राजस्व दाव अंसूल करने के लिए अपने अंतरिक कानून के अंतर्गत अधिकार प्रदत्त हो और कर दस्ता को अंसूल सेकने का और कोई अधिकार प्रदत्त न हो ।
3. इस अनुच्छेद के अनुसरन में एक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंसूल की गई राजि दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अंग्रेजित कर दी जाएगी । तथापि, प्रयोगोन्तरित राज्य के उन सर्वों की प्रतिष्ठानों का इक होगा, यदि कोई हो, जो ऐसी सहायता प्रदान करने के दौरान किए गए हों और यह प्रतिष्ठान उस सीमा तक की जाएगी जिसके लिए दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच में व्यापक सहमति हो गई हो ।
4. इस अनुच्छेद की किसी भी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि दोनों में से किसी एक संविदाकारी राज्य पर यह सहायता लागू की जाए कि वह उन प्रशासनिक उपर्योग से भिन्न तरह के उपर्य करे जो उसके स्वर्य के करों की अंसूली में किए जाते हैं जथवा वह ऐसे प्रशासनिक उपर्य करे जो कि उसकी मार्क्यनिक नीति के प्रतिकूल हो ।

अनुच्छेद - 29

समाप्ति

- सीधिवालकर्ता राज्य इस अधिसमय को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अधिकारीयों के पुरुष किए जाने के बारे में राजनीतिक मायदा से लेखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।
- यह अधिसमय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वही अधिसूचना की प्राप्ति के तीस दिन बाद प्राप्ति हो जाएगा ।
- इस अधिसमय के उपर्योग निम्न प्रकार से प्राप्ति होंगे :

१क। त्रिनिदाड और ट्रेनेगो में :-

१।।। यिस कैलेण्डर वर्ष में यह अधिसमय लागू होता है उसके अगले अनुकूली कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अद्यता उसके बाद अवा की गई अधिक कोडिट की गई आय पर शोत पर रोके गए करों के संबंध में ;

१।।। यिस कैलेण्डर वर्ष में यह अधिसमय लागू होता है उसके अगले अनुकूली कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अद्यता उसके बाद शुरू होने वाले किसी करारेय वर्ष में आय पर अन्य करों के संबंध में ; और

१।।। भारत में, यिस कैलेण्डर वर्ष में यह अधिसमय लागू होता है उसके अगले अनुकूली कैलेण्डर वर्ष में और बाइ के पहले दिन को अद्यता उसके बाद शुरू होने वाले किसी किल्लीय वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

अनुच्छेद - 30

समाप्ति

यह अधिसमय अनिवार्य समय तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसी सीधिवालकर्ता राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी सीधिवालकर्ता राज्य इस अधिसमय के लागू होने की तात्पुरता से लेकर पांच वर्षों की समाप्ति के बाद शुरू हुए किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनीतिक मायदा से समाप्त या नोटिस देकर अधिसमय को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में, यह अधिसमय निम्न के संबंध में विष्फल हो जाएगा :

१क। त्रिनिदाड और ट्रेनेगो में :-

१।।। यिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुकूली कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को अद्यता उसके बाद अवा की गई अधिक कोडिट की गई आय पर शोत पर रोके गए करों के संबंध में ;

iii) निस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुकर्ता कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी करायेय वर्ष में आय पर अन्य करों के संबंध में ;

iv) भारत में, निस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले अनुकर्ता कैलेण्डर वर्ष की पहली अंग्रेजी अथवा उसके बाद के किसी पूर्वकर्ता वर्ष में प्राप्त आय के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधीक्षताकारियों ने इस अधिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

पोर्ट आफ स्पेन में वर्ष एक हजार नौ सौ निन्यानवे के फरवरी माह के आठवें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं । पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ को प्रभावी माना जाएगा ।
भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

श्रिनिडाड और टोबेगो गणराज्य की सरकार की ओर से

(के०एम०आर० जनार्दनन)

(ब्रियां कुई तुंग)

[अधिसूचना सं०11111/99/फा० सं० 503/11/95-एफ०टी०डी०]

विजय माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(FOREIGN TAX DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1999

INCOME-TAX

G.S.R. 720(E).— Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Trinidad and Tobago for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, has entered into force on the thirteenth day of October, 1999, thirty days after the receipt of the later of the notifications by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their laws for bringing into force of the said Convention in accordance with article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF INDIA

AND THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

FOR THE AVOIDANCE OF

DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION

OF FISCAL EVASION WITH RESPECT

TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries have agreed as follows:

ARTICLE 1**Personal Scope**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2**Taxes Covered**

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied,
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation,
3. The existing taxes which are the subject of this Convention are:-
 - (a) in the case of Trinidad and Tobago, the corporation tax, the income tax, the unemployment levy and the petroleum profits tax (hereinafter referred to as "Trinidad and Tobago tax");
 - (b) in the case of India, the income tax, including any surcharge thereon (hereinafter referred to as "Indian tax").
4. This Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed by a Contracting State after the date of signature of this

Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3

General Definitions

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "Trinidad and Tobago" means the Archipelagic State of Trinidad and Tobago, comprising the several islands of Trinidad and Tobago, its archipelagic waters, territorial sea and the airspace thereof, together with the adjacent submarine areas of the Exclusive Economic Zone and the continental shelf beyond the territorial sea over which Trinidad and Tobago exercises sovereign or other rights in accordance with the laws of Trinidad and Tobago and with international law.
 - (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of Trinidad and Tobago or the Republic of India, as the context requires;

- (d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which is a resident of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Trinidad and Tobago, the Minister to whom the responsibility for Finance is assigned or his authorized representative;
 - (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;
- (i) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;

- (i.i) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
- (j) the term "fiscal year" means:
 - (i) in the case of Trinidad and Tobago, the "year of income" as defined in section 2(1) of the Income Tax Act, Chapter 75:01;
 - (ii) in the case of India, "previous year" as defined under section 3 of the Income Tax Act, 1961.
- (k) the term "tax" means Trinidad and Tobago tax or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.

2. In the application of this Convention by a Contracting State any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

ARTICLE 4

Resident

1. For purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer ("centre of vital interests");
 - (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
 - (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
 - (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

ARTICLE 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
 - (g) a sales outlet;
 - (h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (i) a drilling rig or ship used for, or in connection with, the exploration or development of natural resources;
 - (j) a dredging project;
 - (k) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and
 - (l) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith only if such site, project or activity last more than nine months.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character.
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person, other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies, is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3

which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

(b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same control, as that enterprise.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such person is acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State

(whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

Income from Immovable Property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats, motor vehicles and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may also be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year, unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
2. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used in the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.
3. For the purposes of this Article, interest earned incidentally on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9

Associated Enterprises

1. Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

- 2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent

authorities of the Contracting States shall, if necessary, consult each other.

ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected

with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax

in that State provided it is derived and beneficially owned by -

- (i) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) (a) in the case of Trinidad and Tobago, the Central Bank of Trinidad and Tobago, the Agricultural Development Bank, the Export Insurance Company, the National Housing Authority, the National Insurance Board, the Home Mortgage Bank, the Deposit Insurance Corporation, the Small Business Development Company, the Development Finance Limited and the Trinidad and Tobago Mortgage Finance Company;
- (ii) (b) in the case of India, the Reserve Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Export Import Bank of India, the National Housing Bank, the Small Industries Development Bank of India and the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI); or
- (iii) any other institution or agency as may be mutually agreed upon between the two Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, but shall not include any item which is treated as a distribution under the provisions of

Article 10 of this Convention. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest having regard to the debt-claim for which it is paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting

State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

Royalties and Fees for Technical Services

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic or scientific work including cinematograph films or recordings on any means of reproduction for use in connection with television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, know-how, computer software programme, secret formula or process, or any industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;
(b) The term "fees for technical services" means payment of any kind in consideration for the rendering of any managerial, technical or consultancy services including the provision of services by technical or other personnel but does not include payments for services mentioned in Article 14 and 15 of this Convention.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment, or fixed base then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In such case,

the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft shall be taxable only in that State.
4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if his stay in the other State is for a period or periods aggregating 183 days or more in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State; or
- (c) if the remuneration for his activities in the other Contracting State is paid by a resident of that Contracting State or is borne by a permanent establishment or a fixed base situated in that

Contracting State and exceeds in the fiscal year a sum of Rupees 40,000 or its equivalent in Trinidad and Tobago currency.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of medical practitioners, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 salaries, wages, emoluments and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may also be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

ARTICLE 16

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 17

Artistes and Sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may also be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the

activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the visit to that State is substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income is taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

ARTICLE 18

Pensions and Social Security Payments

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment to a resident of a Contracting State and any annuity paid to such a resident may also be taxed in that State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is part of the social security system of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

ARTICLE 19

Government Service

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or

subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20

Students and Apprentices

1. A student or business apprentice who is or was a resident of a Contracting State immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose

of his education or training shall, besides grants, loans and scholarships, be exempt from tax in that other State on:

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
- (b) remuneration from employment in that other State for an amount not exceeding the amount which is exempt from tax under the laws of that other Contracting State for any fiscal year, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefit of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than seven consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

ARTICLE 21

Professors, Teachers and Research Scholars

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research, if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.
4. For the purposes of paragraph 1 "approved institutions" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the State in which the institution is located.

ARTICLE 22

Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6,
 - (a) if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the

provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply;

(b) if the resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in the form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any form or nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

ARTICLE 23

Elimination of Double Taxation

1. The laws in force in either of the Contracting State will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.
2. In the case of Trinidad and Tobago, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Trinidad and Tobago derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in India, Trinidad and Tobago shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in India, whether directly or by deduction at source. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax as computed before the deduction is given, which is

attributable to the income which may be taxed in India.

3. In the case of India, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Trinidad and Tobago, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in Trinidad and Tobago, whether directly or by deduction at source. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Trinidad and Tobago.

4. The tax payable in the Contracting State mentioned in paragraphs 2 and 3 of this Article shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the tax incentives granted under the laws of the Contracting State and which are designed to promote economic development.

5. Income which in accordance with the provisions of this Convention, is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

ARTICLE 24

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements

to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to the residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs or deductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
4. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11 or paragraph 6 of Article 12 apply, interest, royalties and fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly

or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the action of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Convention.
2. The competent authority shall endeavour if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities shall, through consultations, develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article.

ARTICLE 26

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents), as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose

the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 27

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28

Collection Assistance

1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates, together with interest, costs, and

civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a "revenue claim".

2. Request for assistance by the competent authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include a certification by such authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined. For the purposes of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection.
3. Amount collected by the competent authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent authorities of the two States.
4. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy.

ARTICLE 29

Entry into Force

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Convention.

2. This Convention shall enter into force thirty days after the receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in Trinidad and Tobago:

(i) in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after first January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, to income in any taxable year beginning on or after first January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force; and

(b) in India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which this Convention enters into force.

ARTICLE 30

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of this Convention. In such event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in Trinidad and Tobago:

- (i) in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after first January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- (ii) in respect of other taxes on income, to income in any taxable year beginning on or after first January in the calendar year next following that in which the notice is given;

(b) in India in respect of income derived in any previous year on or after the first April next following the calendar year in which the notice is given.

In WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at Port of Spain this 8th day of February, 1999 in English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the Republic of India

.....
(K. M. R. JANARTHANAN)

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

.....
(BRIAN KUEI TUNG)

[Notification No. 11111/99/F.No. 503/11/95-FTD]
VIJAY MATHUR, Jt. Secy.